तीन वर्षों के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी की पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य पत्रों पर अलग-अलग कुल कितनी धनराशि व्यय की है?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shifting of water meters in Laxmi Bai Nagar

456. SHRI ROSHAN LAL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3847 given in the Rajya Sabha on the 11th December, 1987 and state:

(a) what is the number of Government quarters in Laxmi Bai Nagar, New Delhi whose water-meter chambers have since been shifted inside the premises, type-wise; and

(b) by when the same are likely to be shifted in the remaining quarters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) The details, as furnished by the CPWD, are as follows:—

Watermeters shifted inside the premises

Type of the Qrs.	No. of Qrs.
II	26
III	NIL
IV	12

(b) The work will be taken up after the sanctioning of the estimates.

उत्तर प्रदेश द्वारा सूखा राहत का उपयोग

457. **श्री रशीद मसूद :**
श्री अजीत सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1988 के प्रथम सप्ताह तक राज्य इस धनराशि में से केवल 13 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग कर पाया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार को सूखा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए इस शेष धनराशि का तुरन्त उपयोग करने का निर्देश दिया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में सूखा राहत के लिए राज्य सरकार को 155.74 करोड़ रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वे प्रभावित जनसंख्या को कारगर राहत सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करें।

दिल्ली के किसानों को घटिया बीजों की पूर्ति

458. **श्री रशीद मसूद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में इस आशय के समाचार प्राप्त हुए हैं

कि राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा दिल्ली के किसानों को गेहूं के घटिया किस्म के बीजों की पूर्ति की गयी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और क्या सरकार ने घटिया बीजों की पूर्ति के जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि व सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने दिल्ली में रबी 1987-88 के दौरान 3,011 किसानों को गेहूं के बीज सप्लाई किए। ये बीच अंकुरण, शुद्धता तथा अन्य क्वालिटी घटकों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किये गये थे। विवरण के समय ये बीज वैधता की अवधि में थे तथा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते थे। तथापि कुछ किसानों से बीजों के अंकुरण कम होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी तथा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा तत्काल इन मामलों की जांच की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा जांच करने के बाद करीब 20 मामलों में बीजों को बदला गया था।

Drought relief to Orissa

459. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Phulbani, Kalahandi and Bolangir districts of Orissa are the drought prone districts of the State;

(b) whether some more districts of the State have recently been declared as drought prone; and

(c) if so, the details of the Central assistance given so far to the State during 1987 and the drought relief measures undertaken in that State during the same period?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) Phulbani, Kalahandi, Bolangir and Sambalpur are the drought prone districts in Orissa.

(b) No, Sir.

(c) A ceiling of expenditure of Rs. 59.42 crores has been approved for drought relief in Orissa in the wake of post monsoon drought of 1987. The State Government have taken various relief measures such as execution of employment generation works, augmentation of drinking water supply, supplementary nutrition programme, and a special feeding programme for destitutes, old and infirm.

Supply of drinking water to problem villages

460. SHRI JAGADISH JANI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have taken any steps to provide drinking water facilities to all the problem villages;

(b) if so, how many problem villages in the different States have been provided with potable water facilities during 1987-88; and

(c) the target set to provide potable water facilities to the problem villages during 1988-89?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY